Name of the College → APSM College Barauni
Deptt → Economics.
Designation → [G.T]
Date → 30.6.2021

Class - B.A. Part - I
Paper → 2nd

Name of the topic → [भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व]

(iv) तकनीकी सुधार → [Technological Reforms]

⇒ तकनीकी सुधार ⇒ तकनीकी सुधारों के अंतर्गत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का निम्न रूपों में प्रयास किया जाता है।

⇒ उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग → भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास आदि के उत्पादन में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। इन बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये वर्ष 1963 में 'राष्ट्रीय बीज निगम' की स्थापना की गई।

⇒ रासायनिक खाद का प्रयोग → कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। गाँवों में कम्पोस्ट खाद के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है। रासायनिक खादों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि होने लगी है, लेकिन इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है।

⇒ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग → फसलों को बीमारी तथा कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिये कीटनाशक दवाओं के उचित प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। पौधा संरक्षण के लिये एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंध कार्यक्रम को अपनाया गया है।

⇒ वैज्ञानिक कृषि तकनीक → इसमें खेती की पारंपरिक विधियों के स्थान वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर अत्यधिक जोर दिया

Scanned with CamScanner

उनकी किस्मों का चुनाव,
गया है। इसके अन्तर्गत फसलों, उनकी किस्मों का चुनाव, खाद का
भूमि की तैयारी, फसल चक्र, बीजों का चुनाव, खाद को अपनाने के
उचित प्रयोग आदि बेहतर कृषि विधियों को अपनाने के
प्रयत्न किये गए हैं। इस संबंध में गहन कृषि क्षेत्र
प्रोग्राम भी कृषि में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के
लिये शुरू किया गया है।

⇒ खेती के यंत्रीकृत साधन → कृषि कार्यों यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे किसानों को सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिये सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है।

⇒ सामान्य सुधार → [General Reforms]

⇒ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार → कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने अथवा उत्पादकता में ~~वृद्धि~~ वृद्धि करने की दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। देश की विभिन्न भागों में कई बड़ी, माध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गई है।

⇒ साख उपलब्ध करना ⇒ किसानों की बढ़ती साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों की स्थापना की गई। बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक बैंक भी किसानों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी आम बजट में किसानों को साख प्रदान करने हेतु उचित धनराशि आवंटित की जा रही है।

⇒ नियमित एवं संगठित बाजार व्यवस्था → किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं ~~मध्यस्थों~~ मध्यस्थों

शोषण से बचने के लिये एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की गई थी इससे किसानो को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं किसान देश के किसी भी बाजार में किसी कृषि उत्पाद के मूल्य के बारे में जान सकेंगे।

⇒ कीमत समर्थन नीति → किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करते रहने की प्रेरणा देने एवं उन्हे बाजार की अनिश्चितताओं से बचने के लिये सरकार द्वारा 24 कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते है। इसके माध्यम से सरकार किसानों को उनकी उपज के लिये एक न्यूनतम कीमत देने का विश्वास दिलाती है।

⇒ बेहतर भंडारण व्यवस्था → किसानों के पास कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण हेतु उपयुक्त भंडारगृह नहीं होते थे और न ही मंडी के स्तर पर उन्हे किसी प्रकार के भंडारगृह उपलब्ध होते। इस लिये मजबूरी में उन्हें अपने कृषि उत्पादों का विक्रय कम मूल्य पर ही करना पड़ता थे। किसानो की इस समस्या के समाधान के रूप में सरकार द्वारा कई नए भंडारगृहों एवं शीत गृहों का निर्माण कराया जा रहा है।

⇒ व्यापारिक फसलें :→ व्यापारिक फसलें उन फसलों को कहते है, जिन्हे उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। किसान इन फसलों को या तो पूर्ण रूप से बेच देता है अथवा आंशिक रूप से स्व-उपभोग के लिये रखकर शेष को बाजार में बेच देता है। इन फसलों में मुख्य रूप से →

(i) तिलहन फसलें → जैसे → मूँगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी
(ii) शर्करा फसलें → जैसे → गन्ना, चुकंदर
(iii) रेशे वाली फसलें → जूट, कपास, सनई
(iv) पेय फसलें → जैसे → चाय, कहवा

Scanned with CamScanner